

प्रेषक,

मनोज चन्दन,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून

दिनांक 10 जुलाई, 2014

**विषय:-** राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के कार्य सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में वित्तिय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 की आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 में दिये गये निर्देशों के आलोक में एवं उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 281/SEIAA दि0 31 मई, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत "पर्यावरण निदेशालय का गठन" योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड तथा राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तराखण्ड के कार्य संचालन हेतु ₹ 38,03,000/- (₹ अड़तीस लाख तीन हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने के लिए निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्चोरमेंट) नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि SEIAA के व्ययों हेतु वास्तविक व्यय आधार पर यथाआवश्यक ही आहरित की जाएगी।
- (2) बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व वन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित परिव्यय के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। साथ ही पूर्व अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा इसके अतिरिक्त योजना की प्रगति तथा उद्देश्यों की पूर्ति संतोषजनक होने पर ही धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
- (3) आपके निर्धन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
- (5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
- (6) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।
- (7) व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा वन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा वन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः....2



- (8) स्वीकृति के सापेक्ष विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान वित्तिय एवं अन्य नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
  - (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
  - (10) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1407270039 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
  - (11) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यकता अनुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)2011, दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट [www.ua.nic.in](http://www.ua.nic.in) तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
  - (12) आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
  - (13) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति में अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
  - (14) SEIAA को प्रस्तुत होने वाले प्रमाणों में आवेदकों से शुल्क/फीस लिए जाने की व्यवस्था तथा इस हेतु यथोचित नियमावली निर्धारित करने पर तत्काल विचार किया जाय।
- 2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीव परिरक्षण 05-00 पर्यावरण निदेशालय का गठन पर मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।
- 3- यह आदेश वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं०- 36(P)XXVII-4-14 दि० 04 जुलाई, 2014 द्वारा दी गयी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्दन)

अपर सचिव

संख्या- <sup>17825</sup> (1)/X-2-2014, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, देहरादून।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
12. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

(मनोज चन्दन)

अपर सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 1725 IX-2-2014-12(48)/2013

अलोटमेंट आई डी - S1407270039

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -07-Jul-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

- 1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन  
110 - वन्य जीवन परिरक्षण 05 - पर्यावरण निदेशालय का गठन  
00 - पप

Plan Voted			
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	3803000	3803000
	0	3803000	3803000

Total Current Allotment To Head Of The Department in Above Schemes -

3803000

(2)